

प्रेषक,

डी0एस0 गब्याल,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
शहरी विकास निदेशालय,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

शहरी विकास अनुभाग-2

देहरादून: दिनांक-07 जनवरी, 2015

विषय:- जवाहर लाल नेहरू शहरी नवीकरण मिशन (JnNURM) के उपघटक UIDSSMT के अन्तर्गत स्वीकृत मंगलौर पेयजल योजना हेतु धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र संख्या: K-14011/27/2013-UD-1, दिनांक 08.01.2013 एवं व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र संख्या: 59(3)/PFI/2013-1531, दिनांक 19.02.2014 एवं का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिनके माध्यम से भारत सरकार द्वारा JnNURM के उपघटक UIDSSMT के अन्तर्गत मंगलौर वाटर सप्लाई परियोजना स्वीकृत करते हुए केन्द्रांश के रूप में प्रथम किस्त की धनराशि अवमुक्त की गयी है।

2- उपरोक्त के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि JnNURM के उपघटक UIDSSMT के अन्तर्गत स्वीकृत मंगलौर पेयजल योजना हेतु भारत सरकार द्वारा प्रथम किस्त के रूप में अवमुक्त धनराशि ₹1434.88 लाख एवं उक्त के सापेक्ष देय राज्यांश ₹358.72 लाख, इस प्रकार कुल ₹1793.60 लाख (₹ सत्रह करोड़ तिरानवे लाख साठ हजार मात्र) की धनराशि को व्यय हेतु आपके निवर्तन पर निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

- (i) उपरोक्त स्वीकृत धनराशि एस0एल0एन0ए0/शहरी विकास निदेशालय द्वारा कार्यदायी संस्था निर्माण शाखा, उत्तराखण्ड पेयजल निगम, हरिद्वार को योजना के दिशा-निर्देशों के अनुरूप निर्गत की जायेगी।
- (i) योजना का क्रियान्वयन शहरी विकास निदेशालय, उत्तराखण्ड के सतत अनुश्रवण में किया जायेगा।
- (ii) शहरी विकास निदेशालय द्वारा योजनाओं का मासिक आधार पर अनुश्रवण एवं पर्यवेक्षण किया जायेगा तथा भारत सरकार द्वारा स्वीकृत थर्ड पार्टी मॉनिटरिंग एजेन्सी (IRMA) की रिपोर्ट में उल्लिखित बिन्दुओं का संज्ञान लेकर कार्यदायी संस्था से उक्त बिन्दुओं के आधार पर सुधार करवाया जायेगा।
- (iii) योजना के क्रियान्वयन के दौरान कार्यदायी संस्था द्वारा कार्यों का साप्ताहिक रूप से अनुश्रवण कर रिपोर्ट (कार्यस्थल स्थल के फोटोग्राफ सहित) एस0एल0एन0ए0 को प्रस्तुत की जायेगी।
- (iv) योजनाओं की स्वीकृति के समय योजनाओं को पूर्ण करने हेतु निर्धारित समयावधि को दृष्टिगत रखते हुए Project Implementation Schedule (CPM/CPERT/BAR CHART) तैयार किया जाना चाहिए, जिससे Cost Overrun and time over run से बचा जा सके।

- (v) योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित कार्यों को प्रकृति के अनुरूप पूर्ण इकाई के रूप में निर्मित किया जायेगा। कार्य को छोटे-छोटे टुकड़ों में बांटकर कार्य नहीं कराया जायेगा तथा निविदाएं भी इसी के अनुरूप आमंत्रित की जायेगी।
- (vi) उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 के प्राविधानों के अनुसार निविदाएं टू-बिड सिस्टम पर तकनीकी बिड के अन्तर्गत, निर्धारित शर्तों को रखते हुए किया जाय ताकि सक्षम व अनुभवी फर्मों/निविदादाताओं द्वारा ही निविदा प्रक्रिया में भाग लिया जाय तथा उच्च स्तरीय फर्म का चयन किया जा सके।
- (vii) भारत सरकार के द्वारा स्वीकृत उक्त योजना के कार्यों हेतु यह अवश्य सुनिश्चित किया जाय कि उक्त कार्य हेतु किसी अन्य मद से धनराशि न दी गयी हो, यदि दी गयी हो तो उस धनराशि को इस अनुमोदित लागत के सापेक्ष व्यय दिखाकर विभागीय बचत से स्वीकृत बजट को शासन को समर्पित कर दी जाय।
- (viii) स्वीकृत कार्य कराते समय वित्तीय हस्तपुस्तिका, बजट मैनुअल, उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 एवं मितव्ययिता के सम्बन्ध में शासन द्वारा समय-समय पर निर्गत किये गये शासनादेशों एवं उक्त सभी के विषय में समय-समय पर निर्गत किये गये शासनादेशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाये, एकमुश्त प्राविधान के विस्तृत आगणन गठित कर लिये जाये, और इन पर यदि किसी तकनीकी अधिकारी के कार्य कराने से पूर्व का अनुमोदन प्राप्त करना नियमानुसार आवश्यक हो तो कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व उक्त अनुमोदन अवश्य प्राप्त कर लिया जाये।
- (ix) कार्य को भारत सरकार के द्वारा दी गई प्रशासनिक तथा तकनीकी स्वीकृति की सीमा के अन्तर्गत ही पूर्ण किया जायेगा। इस लागत में कोई वृद्धि वित्त पोषण के पैटर्न से इतर राज्य सरकार के द्वारा अनुमन्य नहीं होगा।
- (x) नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों के क्रम में कार्यदायी संस्था द्वारा ठेकेदार के साथ किये जाने वाले Construction Agreement में एक वर्ष का Defect Liability Period तथा 3 वर्ष तक अनुरक्षण की शर्त भी रखी जायेगी।
- (xi) स्वीकृत परियोजनाओं के सम्बन्ध में भारत सरकार द्वारा जारी guidelines/Toolkit में उल्लिखित निर्देशों का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- (xii) शहरी विकास निदेशालय द्वारा कार्यदायी संस्था से परियोजना के उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त कर शासन को उपलब्ध कराये जायेंगे।
- (xiii) स्वीकृत की जा रही धनराशि का दिनांक 31-3-2015 तक पूर्ण उपयोग कर लिया जायेगा।

3- उक्त के संबंध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2014-15 के आय-व्ययक के अनुदान सं०-13 लेखाशीर्षक "4217-शहरी विकास-03-छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास-आयोजनागत-800-अन्य व्यय-01-केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र पुरोनिधानित योजना-04-नगरीय अवस्थापना का सुदृढीकरण (यू०आई०डी०एस०एस०एम०टी०) 80 प्रतिशत के०स०-24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त विभाग के अशा०प०सं०-635/XXVII(2)/2014, दिनांक 06.01.2015 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

संलग्न- एलॉटमेन्ट आई०डी० सं०- S1501130072

भवदीय,

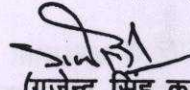
(डी०एस० गब्याल)
सचिव।

सं०- 89 (1)/IV(2)-शा०वि०-2014, तददिनांक।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा परीक्षा), उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. निजी सचिव, मा० मुख्यमंत्री जी/मा० शहरी विकास मंत्री जी, उत्तराखण्ड।
4. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
5. वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून/वित्त अधिकारी, केन्द्रीयकृत भुगतान एवं लेखा (साईबर ट्रेजरी), देहरादून।
6. जिलाधिकारी, हरिद्वार।
7. अपर सचिव, वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
8. अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, उत्तराखण्ड पेयजल निगम, हरिद्वार।
9. वित्त अनुभाग-1 एवं 2/निदेशक, राज्य योजना आयोग, उत्तराखण्ड शासन।
10. निदेशक, एन०आई०सी०, सचिवालय परिसर, देहरादून, को इस अनुरोध के साथ कि नगर विकास के जी०ओ० में इसे शामिल करें।
11. बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, सचिवालय परिसर, देहरादून।
12. अधिशासी अधिकारी, नगरपालिका परिषद, मंगलौर।
13. गार्ड बुक।

आज्ञा से,


(गजेन्द्र सिंह कफलिया)
अनु सचिव।